D.N.A. (Ahmedabad) 31 December, 2016

'GST needs consistency, transparency'

Mismanagement of GST will be a deathblow, warn businessmen

dna correspondent @dnaahmedabad

Ahmedabad: Businessmen have sought consistency and transparency in the implementation of the upcoming Goods and Service Tax (GST) regime in the country, warning that at a time when industrial production in the country is on a downhill, mismanaging the regime could put the economy in a severe mess.

"We need transparency in GST regime. Whether those matters relate to states or to the Centre, there should be no dispute. In the past fifty days, we have seen so many changes. GST regime should avoid such frequent changes," suggested Bhagyesh Soneji, chairperson of Associated Chambers of Commerce and Industry (Assocham) - Gujarat, at a national conference on GST organised by Assocham here on Friday.

"The Index of Industrial Production (IIP) has been dropping for months in succession. If GST fails, trouble would loom over the economy. There could be teething troubles, but they should not be prolonged," she warned in presence of Rohit Patel, minister of state for finance and industries and Mona Khandhar, finance secretary in state government.

Patel advised tax practitioners and businessmen to be transparent in filing returns, or else they could invite trouble. He also allayed businessmen's fears that State GST and Central GST will not violate the principal of 'one country, one tax' as the assessing authority will not change for them.

Petroleum products to come under GST

Ahmedabad: Responding to a demand of businessmen to keep petroleum products within the ambit of GST, state finance secretary Mona Khandar said that petroleum products have been kept out of GST only for two years and would eventually be brought under it ambit.

"Petroleum products constitute about 30-35% of any state's revenues. In Gujarat, its share is a bit higher. It has been kept out of GST for the time being just to ensure that states do not lose out on a major source of income," said Khandar.

'State budget to keep GST at Centre'

Ahmedabad: The state Budget for the fiscal 2017-18 will be prepared keeping in mind that GST will be implemented during the financial year.

"It is possible that the Budget will consider existing taxes for the first six months of the fiscal and GST for the rest," minister of state for finance Rohit Patel said, while interacting with media persons on the sidelines of the seminar.

Earlier, while delivering his address, he had reiterated that GST will be rolled out on April 1, 2017, but will be implemented later on in the year. "The constitutional amendment for GST mandates that it needs to be implemented from September 16 onwards. So be prepared," he said.

Gehri Khoj (Ahmedabad) 31 December, 2016

एसोचैम नें की नकदी निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग

ASSOCHAM

नयी दिल्ली 30 दिसंबर (वार्ता) उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से मांग की है कि 500 रुपये और एक हजार रुपये के पुराने नोट बंद किये जाने के बाद नकदी निकालने की मौजूदा सीमा के कारण आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ रहा है,

इसलिए इस सीमा में इजाफा किया जाना चाहिये । एसोचैम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एटीएम से रोजाना निकासी की सीमा मौजूदा 2,500 रुपये अधिकतम से बढ़ाकर 5,000 रुपये की जानी चाहिये। साथ ही चालू खातों से निकासी की सीमा हर महीने पिछले साल के उसी महीने की तुलना में एक प्रतिशत ज्यादा करने की मांग की गयी है। अभी यह सीमा 50,000 रुपये प्रति सप्ताह है। नोटबंदी की घोषणा करते हुये आठ नवंबर की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से 50 दिन मांगे थे

तथा कहा था उसके बाद स्थिति ठीक हो जायेगी। बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की सीमा आज समाप्त हो रही है। शनिवार से ये नोट सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जमा कराये जा सकेंगे। प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर को फिर राष्ट्र को संबोधित करने की खबर है। इसके मद्देनजर नकदी निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू खातों पर ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ायी जानी चाहिये ताकि नकदी संकट के बावजूद कारोबार का नुकसान न हो। उसने विदेशी पर्यटकों के ,लिए विदेशी मुद्रा को रुपये में बदलने की मौजूदा पांच हजार रुपये प्रति सप्ताह की सीमा को कम बताते हुये कहा है

कि सरकार को इसमें भी इजाफा करना चाहिये । विशेषकर इलाज के लिए भारत आये विदेशी पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । एसोचैम ने कहा कि वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) भी किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण देते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में जिन किसानों के पास चेकबुक नहीं है, वे किस्त अदायगी में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार को एनबीएफसी को पुराने ऋणों की किस्त पुराने नोटों में स्वीकार करने की अनुमति देनी चाहिये। कॉर्पोरेट क्लाइंटों के लिए दैनंदिन की जरूरतों के लिए बैंकों में सामान्य सेवाएं बहाल करने की मांग करते हुये एसोचैम ने कहा कि फिलहाल बैंकों में सामान्य सेवाएं प्रभावित हैं। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में साक्षर करने के लिए व्यापक पैमाने पर मुहिम चलाने की सलाह दी गयी है।

Young Leader (Ahmedabad) 31 December, 2016

एसोचैम ने की नकदी निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग

नयी दिल्ली 30 दिसंबर (वार्ता) उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से मांग की है कि 500 रुपये और एक हजार रुपये के पुराने नोट बंद किये जाने के बाद नकदी निकालने की मौजूदा सीमा के कारण आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस सीमा में इजाफा किया जाना चाहिये।

एसोचैम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एटीएम से रोजाना निकासी की सीमा मौजूदा 2,500 रुपये अधिकतम से बढ़ाकर 5,000 रुपये की जानी चाहिये। साथ ही चालू खातों से निकासी की सीमा हर महीने पिछले साल के उसी महीने की तुलना में एक प्रतिशत ज्यादा करने की मांग की गयी है। अभी यह सीमा 50,000 रुपये प्रति सप्ताह है।

नोटबंदी की घोषणा करते हुये आठ नवंबर की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से 50 दिन मांगे थे तथा कहा था उसके बाद स्थिति ठीक हो जायेगी। बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की सीमा आज समाप्त हो रही है। शनिवार से ये नोट सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जमा कराये जा सकेंगे। प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर को फिर राष्ट्र को संबोधित करने की खबर है। इसके मद्देनजर नकदी निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू खातों पर ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ायी जानी चाहिये ताकि नकदी संकट के बावजूद कारोबार का नुकसान न हो। उसने विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी मुद्रा को रुपये में बदलने की मौजूदा पांच हजार रुपये प्रति सप्ताह की सीमा को कम बताते हुये कहा है कि सरकार को इसमें भी इजाफा करना चाहिये। विशेषकर इलाज के लिए भारत आये विदेशी पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसोचैम ने कहा कि वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) भी किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण देते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में जिन किसानों के पास चेकबुक नहीं है, वे किस्त अदायगी में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार को एनबीएफसी को पुराने ऋणों की किस्त पुराने नोटों में स्वीकार करने की अनुमति देनी चाहिये। कॉर्पोरेट क्लाइंटों के लिए दैनंदिन की जरूरतों के लिए बैंकों में सामान्य सेवाएं बहाल करने की मांग करते हुये एसोचैम ने कहा कि फिलहाल बैंकों में सामान्य सेवाएं प्रभावित हैं। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में साक्षर करने के लिए व्यापक पैमाने पर मुहिम चलाने की सलाह दी गयी है। इसमें भी बैंकों को पहल करनी चाहिये जैसे उन्होंने जनधन खाते खोलने के समय किया था। उद्योग संगठन ने कहा है कि एक साथ प्रचलन में मौजूद 87 प्रतिशत मूल्य की मुद्राओं को अवैध करार देने से अल्पकाल में अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर होगा। हालांकि, अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटनी शुरू होगी। उसने कहा कि मध्यम तथा दीर्घकाल में नोटबंदी के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा।

Gujarat Vaibhav (Ahmedabad) 31 December, 2016

एसोचैम ने की नकदी निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली

उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से मांग की है कि 500 रुपए और एक हजार रुपए के पुराने नोट बंद किए जाने के बाद नकदी निकालने की मौजूदा सीमा के कारण आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर तत्काल बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस सीमा में इजाफा किया जाना चाहिए। एसोचैम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ए.टी.एम. से रोजाना निकासी की सीमा मौजूदा 2,500 रुपए अधिकतम से बढ़ाकर 5,000 रुपए की जानी चाहिए। साथ ही चालू खातों से निकासी की सीमा हर महीने पिछले साल के उसी महीने की तुलना में एक प्रतिशत ज्यादा करने की मांग की गई है। अभी यह सीमा 50,000 रुपए प्रति सप्ताह है। नोटबंदी की घोषणा करते हुए 8 नवंबर की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से 50 दिन मांगे थे तथा कहा था उसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की सीमा आज समाप्त हो रही है। शनिवार से ये नोट सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जमा कराये जा सकेंगे। प्रधानमंत्री के 31 दिसंबर को फिर राष्ट्र को संबोधित करने की खबर है। इसके मद्देनजर नकदी निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू खातों पर ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि नकदी संकट के बावजूद कारोबार का नुकसान न हो।